फोनः-4103333, 2362400 फैक्सः-0141-2373513 वर्षः 73 संख्याः 160 प्रभात जयपुर, मंगलवार 10 जनवरी , 2023 डाक पं.सं. जयपुर सिटी/001/2021-23 पृष्ठ 8 मूल्य 2.50 रु.

ARBIT

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

epaper.rashtradoot.com

राष्ट्रदूत

Metro

Rashtradoot

"Jab Wo Gulam Gaye The Aur Aazaad Laute"

25,000 Boy Scouts from all over the world attended it. The Indian contingent consisted of 165 Boy Scouts from all parts of India.

Hair-friendly Food

A Freak in Space? We've found nothing else out there like our own Solar System

आर्कटिक की गर्म होती जलवायु के साथ ही सैंटा क्लॉज़ का स्लैज खींचने वाले रेनडियर की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। लेकिन सुदूर उत्तर में स्वालबार्ड के रेनडियर फलफूल रहे हैं। यहां गर्म होती जलवायु से हरियाली को प्रोत्साहन मिला है, हरे पौधे ज्यादा दिखने लगे हैं और स्वालबार्ड रेनडियर को ''फैट रिज़र्व'' बनाने का ज्यादा समय मिल रहा है। ऐसा लगता है कि, इन्होंने अपने भोजन में परिवर्तन करना भी शुरु कर दिया है। अब ये बर्फ से बाहर निकलती घास को भी खाने लगे हैं। स्वालबार्ड के रेनडियर लैपलैंड के रेनडियर की तुलना में छोटे और मोटे होते हैं पर इनके सींग (एंटलर्स) सुंदर और बड़े होते हैं। ये रेनडियर स्वालबार्ड द्वीप समूह, जिससे उत्तरी ध्रुव मात्र 500 मील दूर है, के सम्पूर्ण ''नॉन ग्लेसिएटेड'' भाग में वास करते हैं। यह वो क्षेत्र है जहाँ अंतिम हिम युग में बर्फ नहीं थी। परंतु हाल के वर्षों में अन्य आर्कटिक क्षेत्रों की तरह स्वालबार्ड में भी भारी हिमपात होने लगा है और बर्फ के ऊपर बारिश होने की कई घटनाएं हुई हैं जिससे बर्फ और सख्त हो जाती है। इस स्थिति में रेनडियर के लिए जमीन खोदकर भोजन निकालना मुश्किल हो रहा है। रुस में भारी संख्या में रेनडियर के भूख से मरने की खबरें मिली हैं और कैनेडा व अलास्का में कैरीबू (रेनडियर) की आबादी भी कम हो रही है। इन हालात को देखते हुए स्वालबार्ड रेनडियर के लिए चिंता बढ़ गई है। तथापि, हालिया दशकों में स्वालबार्ड द्वीप समूह के सबसे अधिक उपजाऊ भागों में रेनडियर की आबादी बढ़ी है। इनकी आबादी क्यों बढ़ रही है यह जानने के लिए फिनलैंड की युनिवर्सिटी ऑफ ओऊलू की छात्रा, तमारा हिल्तुनेन और उसके सहयोगियों ने, शीतकाल में हर वर्ष एकत्रित किए जाने वाले रेनडियर के रक्त नमूनों का अध्ययन किया। ग्लोबल चेन्ज बायॉलजी में छपे इस शोध में बताया गया है कि, 1995 से 2017 के बीच, जब हिमपात के बाद बारिश होना आम हो गया था, तब यहाँ के रेनडियर के भोजन में बदलाव आया और ये मॉस की बजाय ग्रेमिनॉइड पौधे (घास व सेज) खाने लगे। रिसर्च को सुपरवाइज़ करने वाले प्रोफेसर जैफ्री वैल्कर ने बताया कि, ग्रैमिनॉइड पौधे सख्त बर्फ तोड़कर बाहर निकल आते हैं और रेनडियर के लिए भोजन सहज सुलभ हो जाता है। जमीन का बढ़ता तापमान और रेनडियर के मलमूत्र विसर्जन से ग्रैमिनॉइड्स की ग्रोथ को प्रोत्साहन मिला है, जिससे स्वालबार्ड रेनडियर को और फायदा हुआ है।

भाजपा के हिन्दुत्व के जवाब में विपक्ष ने मण्डल द्वितीय की लहर पर आशाएं टिकाईं

केन्द्रीय सरकार द्वारा जनगणना को 2024-25 तक टालने का निर्णय लेने से विपक्ष को 2024 में होने वाले लोकसभा तक का समय मिल गया, मण्डल द्वितीय को उन्माद तक ले जाने के लिये

- शनिवार को नीतीश कुमार ने जात आधारित जनगणना करने का निर्णय लिया।
- सपा, एन.सी.पी., डी.एम.के., तेलंगाना की टी.आर.एस. पार्टी व छत्तीसगढ़ व झारखण्ड के सत्तारूढ़ दलों ने जात आधारित जनगणना के समर्थन में सार्वजनिक बयान बाजी शुरू कर दी है।
- छत्तीसगढ़ व झारखण्ड ने विधेयक पारित किया है, ओ.बी.सी., एस.टी. तथा इकोनॉमिकली बैकवर्ड के वर्ग के लिये आरक्षण की सीमा बढ़ाने के लिये।
- तथा इससे 76-77 प्रतिशत आरक्षण करने का फैसला कर लिया है।
- उड़ीसा के मु.मंत्री ने भी जात आधारित जनगणना करने की मांग रखी है।
- इस तरह अब इतनी भारी संख्या में राज्यों द्वारा जात आधारित जनगणना का समर्थन करने से मण्डल समर्थक पार्टियों को 2024 के चुनाव तक काफी समय मिल गया है, इस जात आधारित जनगणना को प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाने के लिये।
- जात काफी भावना प्रधान इशू है, अतः भाजपा के हिन्दुत्व के कार्ड को चुनौती देने का सामर्थ्य रखता है।

-श्रीनन्द झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 9 जनवरी। केन्द्र सरकार ने इस निर्णय की जनगणना की कवायद को 2024-25 तक आगे खिसका दिया जाये, के फलस्वरुप विपक्षी दलों को यह सुअवसर मिल गया है कि वे अगले आम चुनावों से पहले मंडल-2 के उन्माद को भड़का सकें।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को जातिगत-सर्वेक्षण शुरु कर दिया, जबकि समाजवादी पार्टी एन.सी.पी., द्रमुक तथा तेलंगाना की भारत राष्ट्र समिति सहित कई अन्य दल भी इसका जोरदार समर्थन कर रहे है। छत्तीसगढ़ तथा झारखंड पहले ही ऐसे बिल पारित कर ही चुके हैं जिनका उद्देश्य ओ.बी.सी., एस.टी. तथा ई.डब्ल्यु.एस. कोटा को बढ़ाना है। एक सर्वे के बाद, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा से दो विधेयक पारित करा लिये थे जिनमें एस.टी. कोटा को बढ़ाकर 32 प्रतिशत करने, ओ.बी.सी. को 27 प्रतिशत, एस.सी. को 13 प्रतिशत तथा ई.डब्ल्यु.एस. के लिये 4 प्रतिशत का प्रावधान किया गया है तथा इस प्रकार कुल कोटा 76 प्रतिशत तक पहुँच गया है। झारखंड विधानसभा भी कुल आरक्षण कोटा को 77 प्रतिशत पहुँचाने के विधेयक पारित कर चुकी है। इन दोनों राज्य सरकारों के उक्त विधेयक संबंधित राज्यपालों अनुसुइया उइकी तथा रमेश बैस के पास अनुमोदन के लिये विचाराधीन हैं। दूसरी तरफ, भाजपा शासित कर्नाटक के राज्यपाल के उस अध्यादेश को मंजूरी दे दी है, जिसमें कोटा की सीमा 50 से बढ़ाकर 56 प्रतिशत कर दी गई है। चूँकि सर्वोच्च न्यायालय ने आरक्षण की ऊपरी सीमा 50 प्रतिशत कर रखी है, इस पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कुछ आपत्तियाँ उठाई हैं। बघेन ने एक ट्वीट में पूछा: ''एक देश, एक संविधान। फिर राज्य के लोगों के बीच यह भेदभाव क्यों?'' ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी जातिगत जनगणना की माँग की है। वर्ष 2013 में, कर्नाटक के

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

28 जनवरी को भीलवाड़ा आएंगे प्र.मंत्री मोदी?

जयपुर, 9 जनवरी (का.सं.)। प्रदेश में 2023 में होने जा रहे वाले विधानसभा चुनाव में की तैयारियों का भाजपा जनाक्रोश यात्राओं से बिगुल बजा चुकी है, वही अब राज्य के गुर्जर समुदाय को साधने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा तय हो गया लगता है। इसके लिए प्रदेश भाजपा की ओर से तैयारियां

- भगवान देवनारायण की एक हजार एक सौ ग्यारहवीं जयंती पर भाजपा गुर्जर वोट बैंक को साधने के लिए गुर्जर बहुल इलाके में यह सभा आयोजित कर रही है।

भी शुरू कर दी गई है । प्रधानमंत्री मोदी की इस दौरे से प्रदेश में चुनावी माहौल बन जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जनवरी को भीलवाड़ा के आसींद आ सकते हैं। भगवान देवनारायण की 1111वीं जयंती पर होने वाले कार्यक्रम में उनके शिरकत करने की संभावना है। भाजपा

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

चीन ने वीज़ा प्रक्रिया में चुस्ती लाने के लिये प्रक्रिया को काफी सरल बनाया

चीन के दूतावास का आकलन है कि शीघ्र ही चीन व भारत के बीच सीधी उड़ानें शुरू हो जायेंगी

- जैसा की विदित ही है, कोविड की महामारी के कारण सीधी उड़ानें 2019 से स्थगित थीं।
- लगभग 23,000 भारतीय विद्यार्थी चीन में पढ़ाई कर रहे हैं।
- इन विद्यार्थियों के अलावा व्यापार व धंधे के संबंध में चीन जाने वाले भारतीयों की संख्या में भारी बढ़ोतरी होगी, यह आकलन है चीनी दूतावास का।
- चीनी दूतावास अब सोमवार से शुक्रवार तक वीज़ा के लिये आवेदन स्वीकार करेगा व प्रोसैस करेगा।
- पर्यटन, पीपुल-टु-पीपुल सम्पर्क बढ़ाने के लिये चीन अब दस तरह के नये वीज़ा और देगा।

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 9 जनवरी। चीन और भारत के बीच सीधी यात्री विमान सेवा शुरू करने को लेकर दोनों देशों में बातचीत चल रही है। दोनों देशों के बीच डायरैक्ट फ्लाइट्स शुरू होने से भारतीय छात्रों, कारोबारियों और चीन में कार्यरत भारतीयों के परिजनों को काफी राहत मिलेगी।

वर्ष 2019 के अंत में जब करोना वायरस का पहली बार वुहान में पता चला था और उसके बाद यह पूरी दुनिया में फैला था, दोनों देशों के बीच डायरैक्ट फ्लाइट्स तभी से स्थगित है।

फ्लाइट्स के नियमित होने को लेकर दिल्ली स्थित चीनी दूतावास बहुत आशान्वित है और वह वीज़ा प्रोसैसिंग में पहले ही तेजी ला चुका है, क्योंकि उसे उम्मीद है कि चीन के वीज़ा के लिए आवेदन करने वाले भारतीय छात्रों की संख्या में वर्ष 2023 में और इजाफा होगा। कारोबार, यात्रा और पारिवारिक यात्रा के लिए चीन आने वाले लोगों की संख्या भी काफी बढ़ने की उम्मीद है। नई दिल्ली स्थित चाइनीज़ वीज़ा सर्विस सैन्टर ने चीन जाने वाले भारतीयों की सुविधा के लिए 9 जनवरी सोमवार से वीज़ा आवेदन स्वीकार करने शुरू कर दिए हैं। यह काम आगामी शुक्रवार तक चलेगा। चीन के नैशनल इमिग्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन ने पर्यटन और विदेश में स्थित मित्रों से मिलने आने के उद्देश्य को

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

जोधपुर हस्तशिल्प उत्सव में गंदगी के ढेर

जोधपुर, 9 जनवरी (कासं)। जोधपुर शहर के रावण का चबूतरा मैदान में चल रहे पश्चिमी राजस्थान हस्तशिल्प उत्सव 2023 में सफाई व्यवस्था बिगड़ी नजर आ रही है। संभाग के सबसे बड़े इस मेले में जोधपुर सहित आसपास के गांवों से भी लोग खरीदारी के लिए पहुंचते हैं, लेकिन यहां लगी हुई स्टाल्स और उनके

- रावण का चबूतरा मैदान में चल रहे इस हस्तशिल्प उत्सव में भारी तादाद में लोग आ रहे हैं पर मेला स्थल पर ना केवल गंदगी के ढेर लगे हैं, बल्कि अव्यवस्था भी है।

आसपास कचरे के ढेर लगे हैं। इससे मेले में आने वाले लोगों को परेशानी हो रही है। सरकारी योजनाओं की जानकारी देने वाली बुक भी अव्यस्थित तरीके से पड़ी है। लोग मेले में लगे फूड स्टाल्स से खाने की चीज़े लेने के बाद प्लेट्स इधर-उधर फेंक रहे हैं । इसके चलते यहां गंदगी हो

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पहली बार राज्यपाल ने अपने द्वारा ''उद्घाटित'' सत्र से बहिर्गमन किया

मुद्दा था, तमिलनाडू सरकार द्वारा विधानसभा में राज्यपाल की कार्यवाही के खिलाफ प्रस्ताव पारित कराना

- राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में सरकार द्वारा भेजे गये, उन अंशों को काट दिया, जिनमें राज्य सरकार द्वारा द्रविड़ मॉडल की विशेषताओं का वर्णन किया था।
- मु.मंत्री स्टालिन का तर्क था कि, राज्यपाल के अभिभाषण को राज्यपाल ने सात जनवरी को स्वीकृति दी थी तथा इसके बाद अभिभाषण की पत्रिका छपी थी तथा विधायकों के लैपटॉप पर भी डाल दी गयी थी।

-लक्ष्मण वेंकट कुची-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 9 जनवरी। यह पहला अवसर है कि किसी राज्य का राज्यपाल उस विधानसभा सत्र से ''वॉक आउट'' कर गया हो, जिसका उसने शुभारम्भ किया हो। तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि विधानसभा के उद्घाटन से ''वॉक आउट'' करने वाले पहले राज्यपाल बने। ऐसा उस समय हुआ, जब राज्य के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने एक प्रस्ताव पेश कर सदन से कहा कि सरकार द्वारा तैयार किया राज्यपाल का मूल अभिभाषण रिकॉर्ड पर लिया जाये तथा अभिभाषण की वे टिप्पणियां डिलीट कर दी जाए जो राज्यपाल ने अलग से की थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यपाल ने गरिमा और मर्यादा का ध्यान नहीं रखा।

वस्तुतः, सोमवार से शुरु हुये तमिलनाडु विधानसभा सत्र के हंगामेदार होने की उम्मीद थी क्योंकि सत्तारूढ़ दल तथा उसके गठबंधन हिस्सेदार रवि के उन सुझावों से बहुत नाराज़ थे, जिनमें उन्होंने राज्य के वर्तमान नाम ''तमिलनाडु'' को बदलकर ''तमिझागम'' कर देने के लिये कहा था। रज्यपाल ने जैसे ही अपना संबोधन शुरु किया था, वैसे ही सत्तारूढ़ गठबंधन के विधायकों ने उनके खिलाफ नारेबाजी शुरु कर दी थी। द्रमुक के गठबंधन पार्टनरों- कांग्रेस, सी.पी.एम. सी.पी.आई. वी.सी.के. तथा कौन्गू नाडु

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

भाजपा कोर कमेटी की बैठक

जयपुर, 9 जनवरी (का.सं.)। राजस्थान में भाजपा के आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा के लिए सोमवार को एक कोर कमेटी की बैठक हुई। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और वरिष्ठ नेता ओम माथुर का नहीं आना चर्चा का विषय रहा। कार्यकर्ताओं में चर्चा रही कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा

- बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और वरिष्ठ नेता ओम माथुर का शामिल नहीं होना कार्यकर्ताओं के बीच चर्चा का विषय बना रहा।

राजे एक बार फिर संगठन को आंख दिखाते हुए और कमेटी की बैठक में शामिल नहीं हुईं । बैठक में आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा की गई।

बैठक के बाद प्रभारी अरुण सिंह ने कहा कि बैठक में जन आक्रोश यात्रा और जन आक्रोश सभा का प्रजेंटेशन

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

जो आलाकमान खुद को चुनौती देने वाले नेताओं पर 100 दिन बाद कार्यवाही करने में असमर्थ है, वह बड़े फैसले कैसे ले पाएगा?

ऐसे में बड़ा सवाल है कि, सचिन पायलट को किस हद तक संतुष्ट करेगी कांग्रेस, या अंतर्द्वंद जारी रहेगा

- प्रभारी रंधावा की अग्नि परीक्षा, चुनावी वर्ष में दोनों खेमों के बीच सामंजस्य बने, लेकिन टास्क मुश्किल, इस पर मुख्यमंत्री और डोटासरा के साथ सोमवार को लंबी चर्चा हुई है।

जयपुर, 9 जनवरी (का.प्र.)। वर्ष 2023 के चुनावी वर्ष में अब कांग्रेस संगठन को चुस्त-दरुस्त करने में जुटी है। हालांकि चाल कछुए जैसी है, तो दूसरी ओर अब चुनावी वर्ष में सचिन पायलट को लेकर पार्टी को निर्णय लेना जरूरी हो गया है। सिर्फ सचिन पायलट को पार्टी की ''असैट'' बताकर चुनावी वर्ष में चले जाएं ,इससे पार्टी का फायदा होने वाला नहीं है, यह बात पार्टी अच्छी तरह से जानती है। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का खेमा नहीं चाहता कि सचिन पायलट किसी भी स्थिति में कोई अहम पद पर आएं। ऐसे में अब पार्टी के अंदर उधेड़बुन चल रही है कि आखिरकार सचिन पायलट को किस पद पर संतुष्ट किया जा सकता है।

राजस्थान में कांग्रेस के नए प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के कार्यभार संभालने के बाद राजस्थान का निरन्तर दौरा कर रहे हैं। वह भारत जोड़ो यात्रा के दौरान यहां आते रहे, वहीं उसके बाद भी लगातार दौरे कर रहे हैं। पिछली बार जब वे जयपुर आए थे, तो उन्होंने कहा था कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच झगड़े खत्म कराना उनका काम है। ऐसे में अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि आखिरकार प्रभारी दोनों नेताओं के बीच कैसे सामंजस्य बिठाते हैं। दरअसल लड़ाई पद की है और सचिन पायलट भले ही खुद कुछ नहीं बोल रहे,लेकिन उनके समर्थकों का सीधा मत है कि 2018 में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनवाने में सबसे बड़ा योगदान सचिन पायलट का था। इसका कारण वे बताते है कि 2013 में जब कांग्रेस की मात्र 21 सीटें आई थी, उसके बाद पायलट ने जो मेहनत की, उसी के नतीजे के रूप में राजस्थान में कांग्रेस की सत्ता आई। ऐसे में उन्हें मुख्यमंत्री पद दिया जाना चाहिए।

इधर वर्तमान में जो परिस्थितियां बनी हुई है,उसमें लगता नहीं है कि कांग्रेस आलाकमान इतना बड़ा फैसला लेने की स्थिति में है। यह बात इसलिए कही जा रही है कि कांग्रेस आलाकमान को सीधे आंख दिखाने वाले नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल, जलदाय मंत्री महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौड़ को नोटिस दिए जाने के 100 दिन के बाद भी कांग्रेस कार्यवाही नहीं कर पाई, ऐसे में क्या

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)